बीके अस्पताल की दुर्दशा से संतुष्ट हैं पीएमओ सविता यादव, प्रशंसा का राष्ट्रीय प्रमाणपत्र जो है

फ़रीदाबाद (म.मो.) साधारण से साधारण डिलिवरी का मामला हो अथवा साधारण फ्रैक्चर आदि के अधिकांश मरीज़ों को रैफ़र करने का काम पूरी लगन से यह मान कर किया जा रहा है कि यह अस्पताल तो बना ही रैफ़र करने के लिये है न कि इलाज करने के लिये। सबसे बढ़ कर, इन दिनों गजब की बात तो यह है कि डायरिया, पेचिश, व पेट दर्द जैसे मौसमी बीमारी से ग्रस्त बच्चों तक का इलाज यहां सम्भव नहीं हो पा रहा। और तो और ओआरएस का घोल व ड्रिप तक का सामान भी मरीज़ों को बाहर से खरीद कर लाना पड़ता है, थोड़ी महंगी व महत्वपूर्ण दवाओं की तो बात ही छोड़ दीजिये।

इस सबके बावजूद पीएमओ डॉ. सविता यादव की बेशर्मी तो देखिये कि अपने अस्पताल की इन सब कमियों को नकारते हुए उल्टे मरीज़ों को ही झूठा बता रही हैं। चौड़े में झूठ बोलते हुए वे कहती हैं कि यहां किसी प्रकार की दवाईयों की कोई कमी नहीं है। आने वाले सभी मरीज़ों को दवाओं सहित बेहतरीन इलाज दिया जा रहा है। लगता है कि झूठ बोलने की प्रेरणा वे देश के राजनैतिक नेतृत्व से लगातार ले रही हैं। अपने झूठ एवं खोखले दावों को कायम रखने के लिये उनके पास बेहतरीन उपाय अपने दफ्तर में ही बैठे रहना है। वे कभी अपने वातानुकूलित कक्ष से बाहर निकलकर मरीज़ों एवं अस्पताल की दुर्दशा को देखना तक पसंद नहीं करती। अस्पताल में पंखे चल रहे हैं या नहीं, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इनका एसी चलते रहना चाहिये।

जाहिर है कि यदि ये डॉक्टर साहिबा अपने कक्ष से निकल कर अस्पताल में

घूमेंगी तो मरीज़ों की दुर्दशा भी नजर आयेगी। इन्हें सामने पाकर मरीज़ अपनी व्यथा-कथा भी इनके सामने रोयेंगे। मरीज़ों से सामना करने से बचने के लिये ही ये अपने कक्ष में बैठ कर ही टाइम पास करती रहती हैं। इनकी इस कार्यशैली के चलते सम्बन्धित स्टाफ़ भी अपने काम के प्रति लापरवाही एवं कोताही बरतने के लिये स्वतंत्र रहते हैं। इसी के चलते अस्पताल में बिजली, पानी व सफ़ाई की व्यवस्था सदैव चौपट रहती है।

अस्पताल में तमाम तरह की कमियों व मरीज़ों की दुर्दशा के बावजूद डॉक्टर सविता का यह कहना कि उनके यहां तो सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, इस बात का दृढ़ संकेत है कि वे इस दुर्दशा को ऐसे ही कायम रखेंगी। रही-सही कसर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र की दो सदस्यीय टीम ने पूरी कर दी है। उनके द्वारा किये गये तथाकथित औचक निरीक्षण में उनहोंने इस अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था को सर्वोत्तम पाकर प्रथम श्रेणी का प्रमाणपत्र भी दे डाला। लगता है कि इस फ़र्जी टीम ने भी पीएमओ के वातानुकूलित कक्ष में बैठकर ही फर्जी रिपोर्ट तैयार करके अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर ली है। इस तरह का फ़र्जीवाड़ा करनेवाली यही अकेली टीम नहीं है, इससे पहले भी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम आई थी जिसने इस अस्पताल को 89 प्रतिशत अंक देकर बहुत बढ़िया होने का प्रमाण पत्र दिया था।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जो अक्सर छापेमारी की नौटंकी करते देखे जाते हैं क्या उन्हें इस अस्पताल में हो रही मरीज़ों की ऐसी-तैसी नज़र नहीं आ रही या वे जान-बूझकर किसी दबाव के चलते धृतराष्ट्र बने बैठे हैं? चलो विज तो दूर बैठे हैं यहां के स्थानीय विधायक मंत्री-संत्री क्यों आंखें बंद किये बैठे हैं?

धनेश अदलखा पर मुकदमा दर्ज, फरार बकरे की मां कब तक खैर मनाती, यह तो होना ही था

फ़रीदाबाद (म.मो.) सत्ता चाहे किसी की रही हो, हरियाणा फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन धनेश की लूट कमाई का जुगाड़ हमेशा बना रहा है। वह राजनेताओं के साथ-साथ अफ़सरों के साथ भी हिस्सा-पत्ती करने में विशेष महारत रखते आये हैं। इस लूट कमाई के बदौलत वे दो बार खुद व एक बार अपनी माताजी को नगर निगम पार्षद बनाने में कामयाब रहे हैं।

खट्टर सरकार आने के बाद तो उनकी कतई पौ-बारह हो गई। प्रशासनिक कामों की दलाली खाने के अलावा खट्टर ने भूमि विकस बैंक का चेयरमैन भी बना दिया था। लेकिन इस पद पर कोई बहुत ज्यादा माल-मलाई नहीं थी। इसलिये खट्टर के आशीर्वाद से धनेश को फार्मेसी काऊंसिल का चेयरमैन बना दिया गया। यहां तो लूट कमाई की बल्ले-बल्ले हो गई। जो भी कोई फार्मेसिस्ट का डिप्लोमा पास कर लेता है उसको इस काऊंसिल से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। किसी अन्य प्रदेश के लाइसेंसधारी फार्मेसिस्ट के लिए हरियाणा में काम करना हो तो अधलखा से लाइसेंस लेना, हरियाणा सरकार ने अनिवार्य कर रखा है।

इतना ही नहीं इन लाइसेंसधारियों को हर पांच साल के बाद अपना लाइसेंस को इसी काऊंसिल से रिन्यू कराना अनावश्यक रूप से अनिवार्य बना रखा है। इसके चलते अधलखा की इस 'दुकान' पर इतनी लम्बी-लम्बी लाइनें लग गईं कि लोगों का वर्षों तक नम्बर ही नहीं आता और जब तक ये लाइसेंस न मिले तो इसकी पढ़ाई-लिखाई सब बेकार। जाहिर है कि ऐसे में कोई भी फार्मेसिस्ट जल्दी से जल्दी लाइसेंस प्राप्त करके काम पर लगने के लिये रिश्वत देने के लिये मजबूर होगा। लोगों की इसी मजबूरी का लाभ उठाकर धनेश ने लाइसेंस जारी करने के रेट 30 हजार से 80 हजार तक रखे हुए थे।

विदित है कि लाइसेंस जारी करने का काम चेयरमेन का न होकर रजिस्ट्रार का होता है। लेकिन धनेश खट्टर से अपने सम्बन्धों के बल पर रजिस्ट्रार एवं अन्य स्टाफ़ पर इस कदर हावी रहता था कि इनसे पूछे बगैर काऊंसिल के दफ्तर में पत्ता तक नहीं हिल सकता था।

अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि धनेश जो लूट कमाई कर रहा था वह खट्टर की छत्र-छाया में ही सम्भव थी। इसी छत्र-छाया की बदौलत धनेश के विरुद्ध आने वाली तमाम शिकायतों को दरकिनार कर दिया जाता था। पिछले दिनों ऐसी ही एक शिकायत की जांच के नाम पर एक आईएएस अधिकारी से लीपा-पोती कराके ठंडे बस्ते में रख दिया गया था। इसका उल्लेख 'मज़दूर मोर्चा' के 12-18 जून के अंक में प्रकाशित किया गया था। लेकिन इस बार कुछ पीड़ित लोगों ने सीधे विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराके भिवानी में धनेश के दो एजेंटों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार करा दिया। इस पर थाना विजिलेंस हिसार ने धनेश व उसके एजेंटों के खिलाफ़ भ्रष्टाचार निरोधक धाराओं के तहत मुकदमा नम्बर 14 दर्ज कर लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिये धनेश फिलहाल फरार है। पुलिस तलाश में छापेमारी कर रही है।

उफनते सीवरों व पेयजल समस्या का इस बार 'पक्का' हल

शहर के पार्कों में लगेगा सीवर का पानी

फ़रीदाबाद (म.मो.) नगर निगम के अति 'बुद्धिमान' अफसरों ने एक तीर से दो शिकार करने की बेहतरीन योजना प्रस्तुत की है। इसके अनुसार जो पेयजल पार्कों की सिंचाई में बर्बाद होता है उसे बचाकर सिंचाई के लिये सीवर का पानी इस्तेमाल किया जायेगा। प्रस्तुत योजना के अनुसार 5 से 10 एकड़ वाले पार्कों में छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी)लगाये जायेंगे, इनसे ग्रीन बेल्ट की भी सिंचाई हो पायेगी। इनकी क्षमता पचास केएलडी तक होगी। सीवेज के शोधित पानी को इस्तेमाल करके शुद्ध पेयजल को बचाना कोई नई बात नहीं है। लगभग तमाम विकसित देशों में इस तकनीक का प्रयोग वर्षों से होता आ रहा है। यहां समझने वाली बात यह है कि उनके शोधित जल व पेयजल देखने व सूंघने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। जब तक बताया न जाये कि कौन सा पेयजल है और कौन सा शोधित तब तक दोनों में अंतर करना असम्भव सा रहता है।

लेकिन इसके विपरीत फ़रीदाबाद नगर निगम की कारगुजारियों को जानने वाले बखूबी समझते हैं कि इनके द्वारा लगाये जाने वाले एसटीपी वैसा ही काम करेंगे जैसा कि मिर्जापुर, बादशाहपुर व प्रतापगढ़ के एसटीपी कर रहे हैं। अब क्योंकि ये तीनों एसटीपी शहर से काफ़ी दूर स्थित हैं इसलिये जनसाधारण को इस बात का ज्ञान नहीं कि इन प्लांटों के चलते आसपास के ग्रामीणों का जीना किस कदर दूभर हो चुका है। उसी आधार पर कहा जा सकता है कि वैसा ही खेला नगर निगम शहर के बीच में भी करने की तैयारी कर रही है। इस योजना को लेकर छोड़े जाने वाले करोड़ों रुपये के टेंडरों व उनके बिल पास करने से अधिकारियों को जरूर मोटा आर्थिक लाभ हो जायेगा।

संदर्भवश सुधी पाठक जान लें कि करीब दस साल पहले भी सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर व टाउन पार्क की सिंचाई हेतु भी ऐसी ही एक योजना बनी थी। इसके लिये सेक्टर 14,15 आदि के सीवेज़ को एक एसटीपी द्वारा शोधित करके इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन जागरूक जनता ने नगर निगम अधिकारियों की 'कार्यकुशलता' को भांपते हुए इस योजना को बीच में ही रुकवा दिया था। नागरिक बखूबी समझते हैं कि इनके डिस्पोजल की कभी मोटर फुकी रहेगी तो कभी केवल तो कभी पाइप लाईन फ़टी होगी। ऐसे में सीवेज़ की न तो निकासी हो पायेगी और न ही शोधन। इसका परिणाम सभी नागरिक भली-भांति समझते हैं।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।